भर्ती परीक्षाओं में ''डमी अभ्यर्थी'' बैठाकर नौकरी पाने वाले 2 दबोचे

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर । राजस्थान में प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और नकल के मामलों पर शिकंजा कसते हुए स्पेशल ऑपरेशन्स ग्रुप (एसओजी) ने राजस्थान लोकसेवा आयोग की वरिष्ठ अध्यापक (माध्यमिक शिक्षा) भर्ती-2022 में डमी अभ्यर्थी बैठाकर परीक्षा पास कराने के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। एसओजी ने इस प्रकरण में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

एसओजी के एडीजी विशाल बसंल ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में भादुओं की बेरी निवासी अशोक कुमार विश्नोई शामिल है, जिसने अपनी जगह डमी अभ्यर्थी बैठाकर वरिष्ठ अध्यापक के पद पर चयन प्राप्त किया था। इसके साथ ही

एक अन्य मामले में सुरतराम मीणा की जगह परीक्षा देने वाले विजयपाल विश्नोई को भी गिरफ्तार किया गया है।

जांच में सामने आया कि अशोक कुमार विश्नोई ने भर्ती परीक्षा के दोनों पेपर स्वयं नहीं दिए। सामान्य ज्ञान एवं शैक्षिक मनोविज्ञान विषय के पेपर में उसने हनुमानाराम को डमी अभ्यर्थी बनाकर परीक्षा दिलवाई थी। हनुमानाराम, जो स्वयं शिक्षक है, को एसओजी पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। मुकदमा दर्ज होने के बाद अशोक दो वर्षों से फरार चल रहा था, जिस पर गिरफ्तारी वारंट के साथ 5 हजार का इनाम घोषित था। इसी प्रकार जांच में यह भी खुलासा हुआ कि सुरतराम मीणा ने विज्ञान विषय के पेपर में

■ **एस.ओ.जी. ने वरिष्ठ अध्यापक (माध्यमिक शिक्षा) भर्ती-2022 को लेकर कार्रवाई की**

महिपाल विश्नोई तथा सामान्य ज्ञान व शैक्षिक मनोविज्ञान के पेपर में विजयपाल विश्नोई को डमी अभ्यर्थी बनाया था। महिपाल को पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि विजयपाल विश्नोई को अब दबोचा गया है। उसकी गिरफ्तारी पर 10 हजार का इनाम घोषित था। एसओजी के अनुसार भर्ती परीक्षा में गडबडी से जुड़े इस नेटवर्क की जांच जारी है और इसमें शामिल अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है।

'पंचायत चुनाव में देरी से 1900 करोड़ के फंड पर संकट'

जयपुर । विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने राज्य की भाजपा सरकार पर पंचायत चुनाव को लेकर गंभीर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भाजपा को न संविधान की परवाह है, न न्यायालय के निर्देशों का सम्मान और न ही ग्रामीण विकास की कोई चिंता है।

जूली ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा 15 अप्रैल तक पंचायत चुनाव कराने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं, लेकिन समय सीमा नजदीक आने के बावजूद राज्य सरकार की ओर से चुनाव की कोई ठोस तैयारी नजर नहीं आ रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि समय पर पंचायत चुनाव नहीं हुए तो केंद्र के वित्त आयोग से मिलने वाले करीब 1900 करोड़ रुपये के फंड के अटकने का खतरा पैदा हो सकता है। उन्होंने कहा कि इस फंड के रुकने से स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन और मनरेगा जैसी महत्वपूर्ण ग्रामीण विकास योजनाएं प्रभावित होंगी, जिसका सीधा असर आम जनता पर पड़ेगा।

यूडी टैक्स वसूली और प्रॉपर्टी सीजर में मनमानी की शिकायतें यूडीएच मंत्री खर्रा के पास पहुंची

जयपुर । राजधानी जयपुर में नगरीय विकास कर (यूडी टैक्स) की वसूली और प्रॉपर्टी सीजर में नगर निगम प्रशासन की खामियों की शिकायत लेकर भाजपा जयपुर शहर के प्रतिनिधिमंडल ने यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा और यूडीएच सचिव रवि जैन से मुलाकात की। इस प्रतिनिधिमंडल में भाजपा के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष सुनील कोठारी, पूर्व जयपुर शहर अध्यक्ष शैलेन्द्र भार्गव, पूर्व महापौर पंकज जोशी, निवर्तमान उप महापौर पुनीत कर्णावट, चित्तौड़गढ़ भाजपा जिला प्रभारी विमल अग्रवाल, जयपुर शहर पूर्व महामंत्री तेज सिंह, पूर्व शहर उपाध्यक्ष अनिल शर्मा, भाजपा नेता मनोज शर्मा और विष्णु जायसवाल शामिल थे।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा 31 मार्च तक यूडी टैक्स पर पेनल्टी और ब्याज में रियायत दी जा रही है। इसके बावजूद स्पैरो कंपनी के कर्मचारी और निगम अधिकारियों के मनमानेपूर्ण एवं अवैध वसूली के रवैये से लोगों में भय व्याप्त है। चार दिन पूर्व में भाजपा का एक प्रतिनिधिमंडल यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा से मिला था, तब मंत्री ने विषय की गंभीरता समझकर तुरंत डीएलबी डायरेक्टर प्रतीक चंद्रशेखर एवं नगर निगम आयुक्त गौरव सैनी को अपने आवास पर बुलाकर यूडी टैक्स वसूली और प्रॉपर्टी सीज़र वाले मामलों में तुरंत सभी प्रकार की विसंगतियां दूर करने के निर्देश दिए थे।

मंगलवार को पुन: भाजपा प्रतिनिधियों ने मंत्री खर्रा ने

यूडीएच मंत्री झाबर सिंह से मुलाकात के बाद भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने सचिव रवि जैन को ज्ञापन दिया।

मुलाकात के बाद यूडीएच सचिव रवि जैन से मिलकर पूरे विषय से अवगत कराया। जिस पर रवि जैन ने डीएलबी डायरेक्टर प्रतीक चंद्रशेखर से चर्चा के बाद प्रतिनिधि मंडल को आश्वस्त किया कि जयपुर में किसी भी व्यक्ति के साथ यूडी टैक्स की वसूली और प्रॉपर्टी सीज़र की अवैध कार्यवाही नहीं की जाएगी। रवि जैन ने कहा कि शीघ्र ही एक मीटिंग बुलाई जाएगी, जिसमे निगम से जुड़े तमाम अधिकारी और स्पेरो कंपनी से जुड़े सभी अधिकारियों को बुलाकर यूडी टैक्स में आ रही समस्याओं और विसंगतियों को दूर किया जाएगा।

मारवाड़ ट्रैवल मार्ट पर मंथन

एफ.एच.टी.आर की ओर से मारवाड़ ट्रैवल मार्ट जोधपुर के आयोजन को लेकर इंटरैक्टिव बैठक की गई।

जोधपुर । फैडरेशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म ऑफ राजस्थान (एफ.एच.टी.आर) ने पर्यटन विभाग के सहयोग से आगामी मारवाड़ ट्रैवल मार्ट जोधपुर के आयोजन को लेकर रणनीतिक इंटरैक्टिव बैठक की। यह पहल महाराजा गज सिंह के मार्गदर्शन में हुई, जिसका उद्देश्य मारवाड़, जोधपुर और पूरे थार क्षेत्र को एक प्रमुख वैश्विक पर्यटन गंतव्य के रूप में स्थापित करना है। यह बैठक आतिथ्य एवं पर्यटन क्षेत्र के प्रमुख हितधारकों के लिए एक सशक्त मंच सिद्ध हुई, जहाँ सभी ने मिलकर इस महत्वपूर्ण आयोजन की रूपरेखा पर विचार-विमर्श किया। मारवाड़ ट्रैवल मार्ट जोधपुर का उद्देश्य पश्चिमी राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, भव्य परिदृश्य एवं उत्कृष्ट आतिथ्य परंपरा को वैश्विक स्तर पर प्रस्तुत करना है।

विशेष रूप से स्थानीय कला, लोक संस्कृति, पारंपरिक विरासत, ग्रामीण जीवन शैली एवं प्रामाणिक पर्यटन अनुभवों को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित किया जाएगा। बैठक में एफ.एच.टी.आर. के अध्यक्ष सुरेन्द्र सिंह शाहपुरा, जोधाना होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स सोसाइटी के अध्यक्ष जे. एम. बूब, राजस्थान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स के अध्यक्ष महेंद्र सिंह राठौड़, ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ जोधपुर के अध्यक्ष गजराज सिंह शेखावत, एफ.एच.टी.आर. के वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र सिंह पचार, महासचिव तरुण बंसल, कोषाध्यक्ष राजेन्द्र सिंह जोधा, राजेश सिंघवी, दीपक परिहार रघुवेन्द्र सिंह प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।

ग्रामीण क्षेत्रों के विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा

जयपुर । पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर व राज्य मंत्री ओटाराम देवासी ने मंगलवार को विभागीय समीक्षा में बजट घोषणाओं की क्रियान्विति को लेकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि सभी बजट घोषणाएं तय समय में पूरी पारदर्शिता के साथ लागू करें। बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास और आमजन से जुड़े मुद्दों पर विशेष चर्चा हुई। मंदिरों को पट्टे वितरण, जन समस्या समाधान शिविर, पंचायतों की नियमित मॉनिटरिंग और ऑनलाइन सिस्टम को मजबूत करने पर जोर दिया गया। साथ ही घुमंतु परिवारों को योजनाओं का लाभ दिलाने के निर्देश दिए गए। मंत्री ने नई पंचायतों के लिए भूमि एवं भवन की व्यवस्था, अतिक्रमण हटाने, जल संरक्षण, स्वच्छता और पॉलिथीन पर रोक के निर्देश दिए। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और योजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन पर भी विशेष जोर दिया गया। उन्होंने वर्ष 2013 में जिला परिषदों द्वारा ली गई लिपिक भर्ती को एक सप्ताह में एसओजी को भेजने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने दी 485 करोड़ रु. के विकास कार्यों की सौगात

■ **राजस्थान युवा शक्ति दिवस पर 9432 युवाओं को कौशल उन्नयन प्रमाण पत्र तथा 403 स्टार्टअप्स को वायबिलिटी गैप फंड के 1145 लाख रु. के चैक बांटे**

जयपुर । मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को जयपुर में शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यिमता से जुड़े लगभग 485 करोड़ रुपये से अधिक विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। मानसरोवर स्थित टैगोर इंटरनेशनल स्कूल में राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की श्रृंखला में आयोजित ''राजस्थान युवा शक्ति दिवस'' में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों के कारण ही राजपूताना की रियासतों का एकीकरण संभव हो सका। सरदार पटेल ने 30 मार्च 1949 को भारतीय नववर्ष की चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को रेवती नक्षत्र इन्द्रयोग में वृहद् राजस्थान की स्थापना की थी। इसीलिए हमने चैत्र शुक्ल प्रतिपदा पर ही राजस्थान दिवस मनाने का निर्णय लिया। इसी क्रम में इस वर्ष 19 मार्च को यह दिवस पूरे प्रदेश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने समारोह में 9432 युवाओं को कौशल उन्नयन प्रमाण पत्र तथा 403 स्टार्टअप्स को वायबिलिटी गैप फंड के 1145 लाख रुपये के चैक वितरित किए। उन्होने कहा कि युवा तरुणाई राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत होती है। भारत दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी वाले देशों में से एक है। युवाओं की ऊर्जा एवं प्रतिभा का उपयोग कर देश दुनिया में सिरमौर बन सकता है। समारोह में उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, विधायक गोपाल शर्मा, बालमुकुंदाचार्य, हमीर सिंह भायल, मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, अतिरिक्त मुख्य सचिव कौशल एवं उद्यिमता संदीप वर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधि व आमजन मौजूद थे।

राजस्थान के प्राचीन सिक्के और मुद्राओं की प्रदर्शनी

जयपुर। राजस्थान दिवस समारोह-2026 के उपलक्ष्य में 17 से 19 मार्च तक हवामहल स्मारक में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग की ओर से राजस्थान के प्राचीन सिक्के और मुद्राओं की प्रदर्शनी लगाई गई है। जिसके अंतर्गत विभिन्न कॉल खण्डों की मुद्राओं को पर्यटकों के अवलोकन हेतु प्रदर्शित किया गया है। इस प्रदर्शनी में पंचमार्क, इंडो ग्रीक, ढलित, योद्धेय गणराज्य, जनजातीय, कुषाण, उत्तर कुषाण, पश्चिम क्षत्रप, गुप्तकालीन, इण्डो-ससेनियन, गधैया, आदिवराह, , घुड़सवार-नदी शैली, अजयदेव चौहान, सोमलदेवी, कलचुरी, दिल्ली सल्तनत, मुगल, उत्तर मुगल,

जौनपुर सुल्तान, गुजरात सुल्तान, ईस्ट इंडिया कपनी, ब्रिटिश, जयपुर के झाड़शाही सिक्के, विभिन्न मेडल और टोकन, नजरी एवं देशी रियासतों में बूंदी एवं बीकानेर इत्यादि प्रदर्शित किया गये। यह प्रदर्शनी पर्यटकों एवं शोधार्थियों के लिए लाभदायक सिद्ध होगी।

सार-समाचार

जवाहर कला केन्द्र में कला मेला शुरू

जयपुर । उपमुख्यमंत्री तथा पर्यटन, कला-साहित्य एवं संस्कृति तथा पुरातत्व मंत्री दिया कुमारी ने मंगलवार को जवाहर कला केंद्र स्थित शिल्पग्राम में राजस्थान ललित कला अकादमी द्वारा आयोजित कला मेले का शुभारम्भ किया। यह कला मेला 21 मार्च तक चलेगा जिसमें आमजन का नि:शुल्क प्रवेश है। उपमुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि राज्य सरकार की घोषणा अनुसार इस बार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को 19 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जा रहा है। समारोह के अंतर्गत पर्यटन, कला-साहित्य एवं संस्कृति तथा पुरातत्व विभाग की ओर से 14 मार्च से 19 मार्च तक लोक संस्कृति से परिपूर्ण विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। जिसके तहत आज इस कला मेले का शुभारंभ हुआ है। कला-साहित्य एवं संस्कृति विभाग की उप सचिव तथा जवाहर कला केंद्र की अतिरिक्त महानिदेशक डॉ. अनुराधा गोगिया ने बताया कि यह कला मेला जवाहर कला केंद्र में 17 मार्च से 21 मार्च तक चलने वाला यह मेला राजस्थान ललित कला अकादमी द्वारा क्यूरेटेड किया गया है। मेले में पारंपरिक और समसामयिक कला गतिविधियां आयोजित की जा रही है। जिसमें लगभग 100 से अधिक स्टॉल कलाकारों को आवंटित की गई हैं। जिनके माध्यम से विभिन्न कलाओं का प्रदर्शन किया जा रहा है।

30 हजार फूड हैंडलर्स को प्रशिक्षण

जयपुर । चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर के निर्देशन में खाद्य सुरक्षा आयुक्तालय ने दो दिन में 50 हजार खाद्य कारोबारियों एवं इससे संबंधित व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने का कीर्तिमान बनाने की महत्वपूर्ण पहल की है। इसके तहत पहले ही दिन मंगलवार को 30 हजार से अधिक व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया, जो कि एक रिकॉर्ड है। प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि राज्य में खाद्य सामग्री में मिलावट पर रोकथाम के लिए शुद्ध आहार-मिलावट पर वार अभियान चलाकर रिकॉर्ड कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। खाद्य सुरक्षा आयुक्त डॉ. टी. शुभमंगला ने बताया कि पहले दिवस में ही पूरे राजस्थान में 30 हजार से अधिक फूड हैंडलर्स को ट्रेनिंग दिलाकर रिकॉर्ड बनाया गया है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिड-डे मील कर्मी, राजकीय छात्रावासों के स्टाफ, जेल रसोई कर्मचारी, होटल एवं ढाबा संचालक व स्ट्रीट फूड वेंडर्स सहित विभिन्न खाद्य व्यवसाय से जुड़े व्यक्तियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। विभाग द्वारा इस उपलब्धि को विश्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने हेतु आवश्यक प्रक्रिया प्रारंभ की गई है।

गांधी वाटिका में चित्रकला प्रतियोगिता

जयपुर । गांधी वाटिका संग्रहालय जयपुर में बुधवार प्रात: 11 बजे से राजस्थान दिवस समारोह एवं वन्दे मातरम 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन होगा। इस प्रतियोगिता की थीम ''वन्दे मातरम् 150 वां वर्ष एवं ऐतिहासिक राजस्थान'' रखी गई है। प्रतियोगिता में विभिन्न विद्यालयों, महाविद्यालय एवं संस्थाओं के विद्यार्थी शामिल होंगे, सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किया जाएंगे। प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर रहने वाले प्रतिभागियों को पुरुस्कृत किया जायेगा।

कांस्टेबल कमलेश ने दिखाई ईमानदारी

जयपुर । जालूपुरा थाना इलाके में 16 मार्च को समय रात्रि गश्त के दौरान पुलिस नियंत्रण कक्ष आयुक्तालय जयपुर से छोटू नामक व्यक्ति निवासी मुरैना (मध्य प्रदेश) का पर्स जिसमें 50-60 हजार रुपये थे, जो वनस्थली मार्ग पर गुम हो जाने की सूचना प्राप्त होने पर पुलिस थाना जालूपुरा के कांस्टेबल कमलेश कुमार मय चालक के वनस्थली मार्ग पहुँचकर, सम्बन्धित व्यक्ति से पूछताछ की तो उसने बताया कि वह सिंधी कैम्प से प्राइवेट बस में बैठने के लिये वनस्थली मार्ग आ रहे थे। इस दौरान उसकी पत्नी का पर्स मय नगद रुपये के गुम हो गया। इस पर कांस्टेबल कमलेश कुमार द्वारा सघन चैकिंग की जाकर सम्बन्धित बस में यात्रा करने वाले व्यक्तियों से पूछताछ करते हुए संभावित वनस्थली मार्ग पर पर्स को तलाश किया गया तो गुमशुदा पर्स खाटू श्याम मंदिर के पास रोड किनारे पर पडा मिला। जिसे उक्त दम्पति व्यक्तियो से राशि की पहचान करवाकर पर्स यात्री दम्पति के होना पाया जाने पर पुलिस थाना जालूपुरा लाकर सम्बधित को सुपुर्द किया गया। पुलिस उपयुक्त उत्तर करण शर्मा ने बताया कि कांस्टेबल कमलेश कुमार द्वारा ईमानदारी पूर्ण कार्य करने पर आमजन में पुलिस विभाग की छवि उज्ज्वल हुई है। इस पर कांस्टेबल के उज्जवल भविष्य की कामना व ईमानदारी पूर्ण कार्य करने फलस्वरूप 11 हजार हजार रुपये नकद पुरस्कार मय प्रशंसा पत्र प्रदान किया।

राज्य में कोई वित्तीय संकट नहीं, दुष्प्रचार की राजनीति कर रही कांग्रेस : चतुर्वेदी

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर । राज्य में कोई वित्तीय संकट नहीं है, कांग्रेस द्वारा केवल राज्य सरकार के खिलाफ गलत आंकड़ो, भ्रामक जानकारी एवं दुष्प्रचार की राजनीति की जा रही है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली द्वारा सरकार पर कर्ज, जीएसडीपी, एसएएससीआई योजना एवं केंद्रीय करों में राज्य को कम राशि प्राप्त होना बताया जा रहा है, जबकि हकीकत इससे परे है। राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने आंकड़ों के साथ जानकारी देते हुए कहा कि वर्ष 2018-19 तक राज्य पर 3 लाख 11 हजार 374 करोड़ रुपये का कर्जभार था। वहीं, उदय योजना के अन्तर्गत लिये गये कर्ज 60 हजार 422 करोड़ रुपये को कम करने पर राज्य के गठन से वर्ष 2018-19 तक 2 लाख 48 हजार 952 करोड़ रुपये का ऋण लिया गया था। जबकि गत कांग्रेस सरकार ने वर्ष 2019-20 से वर्ष 2023-24 तक केवल 5 वर्षों में इससे अधिक ऋण 2 लाख 56 हजार 911 करोड़ रुपये अतिरिक्त कर्ज लेकर राज्य को कर्जभार के जाल में फंसा दिया। चतुर्वेदी ने

■ **'राज्य की प्रति व्यक्ति आय बढ़कर 2 लाख 2 हजार 349 रुपये हुई, जबकि कांग्रेसराज में 1 लाख 67 हजार 27 रुपये थी'**

बताया कि गत कांग्रेस सरकार द्वारा 5 वर्षों में जीएसडीपी का औसत 37.83 प्रतिशत ऋण लिया गया था। पूववर्ती कांग्रेस सरकार के छोड़े गये दायित्वों के भुगतान के बावजूद भी राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2026-27 में ऋण को जीएसडीपी के 36.80 प्रतिशत रखा जाना प्रस्तावित किया है, जो कि द्वारा अनुमत सीमा 38.20 प्रतिशत से कम है। गत तीन वर्षों में जीएसडीपी का औसत ऋण 37.49 प्रतिशत रहा है। इसके अलावा गत कांग्रेस सरकार के 5 वर्षों में स्थिर मूल्यों पर जीएसडीपी औसत वृद्धि दर केवल मात्र 5.3 प्रतिशत रही थी, जबकि भाजपा सरकार द्वारा किये गये आर्थिक सुधारों के से राज्य विकास पथ पर चल पड़ा है।

'कोमा में चल रहे पुलिस कांस्टेबल का असमर्थता अवकाश स्वीकृत करें'

जयपुर । राजस्थान हाईकोर्ट ने ड्यूटी के दौरान हुए एक्सीडेंट के चलते 2021 से कोमा में चल रहे पुलिस कांस्टेबल व उसके परिजनों को राहत दी है। अदालत ने राज्य सरकार को उसका विशेष असमर्थता अवकाश स्वीकार करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही राज्य सरकार को कहा है कि वह चार सप्ताह के भीतर अगस्त 2021 से उसे लगातार वेतन का भुगतान करे। जस्टिस आनंद शर्मा ने यह आदेश पुलिस कार्मिक नरेन्द्र सिंह की पत्नी शारदा कंवर की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया। याचिका में अधिवक्ता लक्ष्मीकांत मालपुरा ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता के पति ऑन ड्यूटी 22 अगस्त 2021 को मोटरसाइकिल का टायर फटने से दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे। इस हादसे में उसके सिर में गंभीर चोट आई और वह कोमा में चले गए और वह 85 फीसदी तक दिव्यांग हो गए। याचिका में कहा गया कि दो साल अस्पताल में भर्ती रहने के बाद से उनका घर पर ही उसका इलाज जारी है। इस दौरान उसकी याचिकाकर्ता ने पुलिस विभाग को पत्र लिखकर उसके पति का वेतन व विशेष असमर्थता अवकाश मंजूर करने का आग्रह किया।

भूमि संकट के बीच अंतिम संस्कार स्थलों पर राष्ट्रीय नीति की मांग तेज

इम्पीरियल चैम्बर की पहल पर राज्यसभा में सांसद डॉ. अजीत गोपछड़े ने शून्यकाल में उठाया मुद्दा

जयपुर । इम्पीरियल चैंबर ने ''कब्रिस्तान और ज़मीन का संकट: क्या भारत में भविष्य के टकराव की नींव रख सकता है?'' विषय को 12 जनवरी को सरकार के समक्ष उठाया था। राज्यसभा में महाराष्ट्र के सांसद डॉ. अजीत गोपछड़े ने इस विषय को प्रमुखता से मंगलवार को शून्य काल में उठाया। उन्होंने देश में तेजी से बढ़ते शहरीकरण और सीमित भूमि संसाधनों के बीच इस मुद्दे की गंभीरता को उजागर किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में भूमि एक अत्यंत बहुमूल्य संसाधन बन चुकी है और इसके दीर्घकालिक एवं व्यवस्थित उपयोग के लिए ठोस नीति बनाना आवश्यक है।

उन्होंने सुझाव दिया कि देश के सभी श्मशान घाटों और कब्रिस्तानों की जियोग्राफिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम आधारित डिजिटल मैपिंग अनिवार्य की जाए, जिससे इन स्थलों का सटीक और अद्यतन रिकॉर्ड उपलब्ध हो सके। साथ ही जहाँ पुराने रिकॉर्ड और वास्तविक स्थिति में अंतर है, वहां लैंड ऑडिट कर भूमि अभिलेखों को दुरुस्त करने की आवश्यकता बताई। अपने वक्तव्य में उन्होंने अंतरराष्ट्रीय उदाहरणों का भी उल्लेख किया, जहाँ जापान और यूरोपीय देशों में 'वर्टिकल क्रिमेट्रीज़' और पर्यावरण अनुकूल अंतिम संस्कार प्रणालियाँ अपनाई जा

रही हैं। इसी प्रकार अन्य देशों में सरल और व्यवस्थित व्यवस्थाएँ भी लागू हैं, जिन्हें भारत में भी अपनाने पर विचार किया जा सकता है। संसद में इस विषय के उठने से यह स्पष्ट है कि चैंबर द्वारा उठाए गए मुद्दे अब नीति-निर्माण के केंद्र में आ रहे है।

उन्होंने कहा कि यह विषय किसी एक धर्म या समुदाय से जुड़ा नहीं है, बल्कि देश के बहुमूल्य संसाधनों के संतुलित और जिम्मेदार उपयोग से संबंधित है। सभी परंपराओं का सम्मान करते हुए भविष्य की पीढ़ियों के लिए भूमि एवं पर्यावरण का संरक्षण आवश्यक है। ज्ञात रहे कि इस विषय को सबसे पहले राष्ट्रदूत समाचार पत्र ने 12 जनवरी 2026 को प्रकाशित किया था।

'सरसों-चना की एम.एस.पी. खरीद में अनियमितताएं नहीं होंगी बर्दाश्त'

गड़बड़ी मिली तो उप रजिस्ट्रार होंगे जिम्मेदार, अतिरिक्त रजिस्ट्रार खंड पर भी होगी कार्रवाई : सहकारिता मंत्री

जयपुर (कासं)। सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार दक ने कहा कि राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप किसानों को उनकी उपज का उचित दाम मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि आगामी दिनों में होने वाली सरसों और चना की खरीद में पूर्ण पारदर्शिता बरती जाए। किसी भी तरह की अनियमितता या लापरवाही सामने आने पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। सहकारिता मंत्री मंगलवार को अपेक्स बैंक सभागार में विभाग की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

बैठक में एमएसपी खरीद, सहकारी समितियों की ऑडिट प्रगति एवं आमसभा, सहकारी अधिनियम की धारा 55 एवं 57 के अंतर्गत लम्बित प्रकरण, जनसुनवाई के प्रकरण, विभागीय योजनाओं की प्रगति आदि की विस्तार से समीक्षा की गई। श्री दक ने निर्देश दिए कि एमएसपी पर सरसों-चना की खरीद प्रक्रिया बिना शिकायत सम्पन्न हो। जिन खरीद केंद्रों पर पूर्व में अनियमितताएं सामने आई हैं, उन पर विशेष निगरानी रखी जाए। साथ ही, फर्जी रजिस्ट्रेशन करने वालों पर भी सख्त कार्रवाई की जाए। अनियमितताओं पर रोक लगाने के लिए किसानों से भी निरन्तर फीडबैक लिया जाए। उन्होंने कहा कि खरीद में गड़बड़ी हुई तो उप

सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दक ने मंगलवार को विभाग की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक ली।

रजिस्ट्रार जिम्मेदार होंगे तथा अतिरिक्त रजिस्ट्रार (खंड) के विरुद्ध भी लापरवाही बरतने पर कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए कि उप रजिस्ट्रार और राजफेड के क्षेत्रीय अधिकारी प्रतिदिन खरीद केंद्रों का निरीक्षण करें।

सहकारिता मंत्री ने सहकारी अधिनियम की धारा 55 एवं 57 के अंतर्गत लम्बित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि जिन प्रकरणों में जांच में गबन और अनियमितताएं प्रमाणित हो चुकी हैं, उनमें दोषियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवाई जाए तथा प्रकरण में गंभीरता से कार्यवाही करते हुए चालान पेश करवाया जाए। उन्होंने धारा 55 के अंतर्गत जांच शुरू करते ही न्यायालय में आवश्यक रूप से कैवियट लगाने के भी निर्देश दिए। श्री दक ने कहा कि सोसायटियों में गबन-घोटालों पर रोक लगाने के लिए उनकी ऑडिट और आमसभा समयबद्ध रूप से सम्पन्न करवाई जाए तथा इसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। उन्होंने सभी समितियों में 30 अक्टूबर से पूर्व आमसभा अनिवार्य रूप से करवाने के निर्देश दिए। साथ ही, ऑडिट और आमसभा का डेटा मासिक रूप से तैयार करने के भी निर्देश दिए।

दक ने निर्देश दिए कि संस्थाओं के पंजीयन बिना किसी देरी और परेशानी के होने चाहिए। इस संबंध में निरन्तर फीडबैक लिया जाए और शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाए। उन्होंने सभी जिला उप रजिस्ट्रार को क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटियों का भी नियमित रूप से निरीक्षण कर उनकी ऑडिट व आमसभा तथा नियमों की पालना सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए। सहकारिता मंत्री ने सूचनाएं प्राप्त करने के लिए सभी जिलों में नोडल अधिकारी नियुक्त करने, अधिक से अधिक संख्या में नई सहकारी समितियों का गठन करने तथा गोदाम निर्माण हेतु जमीन चिन्हित कर आवंटन करवाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भूमि विकास बैंकों के ऋणी सदस्यों के लिए संचालित की जा रही एकमुश्त समझौता योजना से अधिक से अधिक पात्र ऋणियों को लाभान्वित किया जाए। उन्होंने मंत्री कार्यालय के समक्ष लंबित जनसुनवाई के प्रकरणों की अनुभागवार विस्तार से समीक्षा करते हुए उनके निस्तारण में गति लाने के भी निर्देश दिए। सहकारिता विभाग की शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां आनन्दी ने निर्देश दिए कि सभी अधिकारी एमएसपी खरीद को सर्वोच्च प्राथमिकता में रखें। उन्होंने कहा कि फील्ड अधिकारियों को प्रतिदिन बताया जाएगा कि उन्हें किस खरीद केंद्र की चेकिंग करनी है। क्रय-विक्रय सहकारी समितियों के मैनेजर हर वक्त मुख्यालय पर उपस्थित रहेंगे। किसी भी प्रकार की शिकायत पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी।

■ **गबन और अनियमितताओं के प्रकरणों में दर्ज करवाई जाए एफआईआर : दक**

■ **सोसायटियों की आमसभा 30 अक्टूबर तक अनिवार्य रूप से कराने के निर्देश**